

रोहित आर्य मामले में नया मोड़, 'स्वच्छता मॉनिटर' प्रोजेक्ट को इस साल मंजूरी नहीं: शिक्षा विभाग का खुलासा

जमीर काज़ी

मुंबई: पवई की इमारत में १७ छोटे बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य मामले में अब एक नया मोड़ आया है। सरकार के बकाया दो करोड़ रुपये के बिल के लिए आर्य ने यह कृत्य किया, ऐसा उसने वीडियो में कहा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसका खंडन किया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रोहित ने 'स्वच्छता मॉनिटर' प्रोजेक्ट के पैसे के लिए पहले कई बार आंदोलन किए थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। उन आंदोलनों के दौरान तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर विवाद के केंद्र में आए थे। इसी प्रोजेक्ट के पैसे मिलने के लिए आर्य ने बार-बार प्रयास किए थे, ऐसा कहा जा रहा है।

इस साल प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं: मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा उपक्रम के तहत शुरू किए गए 'स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट' को महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले २७ सितंबर २०२२ और फिर ३० जून २०२३ को मंजूरी दी थी। लेकिन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्ष के लिए इस प्रोजेक्ट को कोई नई मंजूरी नहीं दी गई है, ऐसा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है। इस फैसले से स्कूलों में स्वच्छता की ग्रैंडिंग व्यवस्था, 'स्वच्छता मॉनिटर' और स्कूलों को मिलने वाले पुरस्कार फिलहाल बंद हैं।

यह उपक्रम आखिर था क्या?: मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा उपक्रम के तहत शुरू 'स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट' स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में कुछ छात्रों या विभागों को स्वच्छता मॉनिटर नियुक्त किया जाता था। उनका मुख्य काम था स्कूल में स्वच्छता नियमों का पालन सुनिश्चित करना, जैसे थूकना, कचरा फेंकना या गंदगी करना पर नियंत्रण रखना।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना और देखकर भी अनदेखा न करना की आदत का प्रचार करना था। 'लेट्स चेंज' नारे के तहत यह प्रोजेक्ट अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क कंपनी के जरिए चलाया जा रहा था। साथ ही, स्कूलों से ५०० से २,००० रुपये पंजीकरण शुल्क लिया गया, यह जानकारी कुछ शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर दी।

इस उपक्रम को पहले २७ सितंबर २०२२ और फिर ३० जून २०२३ को मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी सीएसआर फंड से थी और उस चरण में कुल ९.९ लाख रुपये के भुगतान की नोटिंग है। २०२३-२४ में 'फेज-२' के तहत २ करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ, लेकिन उसकी कार्यान्वयन नहीं हुई।

रोहित आर्य को हटाने के बाद क्या हुआ?: इस प्रोजेक्ट के निदेशक रोहित आर्य का नाम कुछ गंभीर मामले में आने के बाद शिक्षा विभाग ने अगले साल की मंजूरी रोक दी। २०२४-२५ के लिए मंजूरी अस्वीकार करते हुए विभाग ने स्कूलों से ली गई फीस वापस करने के निर्देश दिए और संस्था से अपेक्षित दस्तावेज न आने पर आगे की कार्रवाई भी रोक दी। नतीजतन स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट फिलहाल अनधिकृत स्थिति में है। साथ ही कल हुए आर्य मामले के बाद शिक्षा विभाग ने इस साल संबंधित प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी, ऐसा खुलासा किया है।

पुलिस द्वारा हत्या: एडवोकेट सातपुते रोहित आर्य पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, इसलिए इस पर संदेह उठाया जा रहा है। उसका किया कृत्य गलत था, फिर भी उसे छाती में गोली मारने के बजाय पैर में गोली मारकर घायल किया जा सकता था, इसलिए पुलिस ने उसकी हत्या की है, ऐसा आरोप वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते ने लगाया है। इस संबंध में पुलिस और संबंधित नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सरकार द्वारा कार्रवाई न होने पर इसके खिलाफ याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर नाराजगी जताते हुए महायुती सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हजारों करोड़ के ठेकेदारों के बिल लंबित होने से उनसे ऐसे कृत्य दोबारा होने का खतरा पैदा हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा।

ढाका हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार करो परिवार वालों का एसपी दफ्तर के सामने धरना

बीड। प्रतिनिधी

यश ढाका हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार गणेश शिराले पर अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मनसे और ढाका परिवार ने शुक्रवार को सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया।

शिराले शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख होने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और बीड पुलिस उन्हें भैजेज कर रही है, ऐसा गंभीर आरोप आंदोलनकारियों ने लगाया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला राज्य उपाध्यक्षा वर्षा जगदाले सहित देवेंद्र ढाका और उनके परिवारजन शामिल हुए। घटनास्थल पर मौजूद और आरोपियों की मदद करने वाले सभी को आरोपी बनाया जाए, इस मामले की एसआईटी से जांच हो, तथा आरोपियों की नार्को टेस्ट की जाए-ये प्रमुख मांगें इस दौरान की गईं। एसपी दफ्तर के ठीक सामने आंदोलन होने से पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में अब ३ नवंबर को जिला अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला जाएगा। पुलिस पर लग रहे इन आरोपों से आम जनता में विश्वास कम होता जा रहा है। पुलिस निरीक्षक शीतलकुमार बल्लाळ ने दो बार समझाने की कोशिश की, फिर भी आंदोलनकारी नहीं हटे। नतीजतन, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। दोपहर बाद यह आंदोलन वापस लिया गया।

चुनाव आयोग के खिलाफ आज मुंबई में सत्य का मोर्चा! ईक्विम और फर्जी मतदाताओं के खिलाफ विपक्ष एकजुट

रिपोर्ट - जमीर काज़ी, मुंबई

ईवीएम मशीन घोटाले और राज्य की मतदाता सूची में घपले, डुप्लीकेट तथा फर्जी मतदाताओं के विरोध में महाविकास आघाड़ी, मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) और अन्य सर्वदलीय संगठन शनिवार (१ नवंबर) को मुंबई में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ सत्य का मोर्चा निकालने जा रहे हैं।

यह मोर्चा दोपहर १ बजे फैशन स्ट्रीट से शुरू होगा। इसमें वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ सहित महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे।

इस आंदोलन के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये के विरोध में सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि -

जब तक मतदाता सूची की खामियां दूर नहीं होतीं, तब तक स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव न कराए जाएं।

चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की रणनीति इस मोर्चे में शिवसेना (ठाकरे गुट), राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट), कांग्रेस और मनसे शामिल हैं।

महाविकास आघाड़ी और मनसे की संयुक्त मांग है कि -

जब तक मतदाता सूची पूरी तरह स्वच्छ नहीं होती, तब तक राज्य में चुनाव न हों।

मोर्चा खत्म होने के बाद सभी विपक्षी दल एक संयुक्त घोषणा करेंगे।

अगर राज्य चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं को सूची से नहीं हटाया, तो विपक्ष कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दे रहा है।

न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी विपक्षी दल अब इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।

ठाकरे गुट के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची में गड़बड़ी और फर्जी मतदाताओं का मुद्दा कोर्ट में उठाया जाएगा और इसके लिए याचिका दाखिल की जाएगी।

साथ ही, यह भी मांग की जाएगी कि जब तक राज्य चुनाव आयोग इन त्रुटियों को दूर नहीं करता, तब तक चुनाव स्थगित किए जाएं।

हाल की सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने तीन से चार विकल्पों पर चर्चा की -

१. न्यायालय में याचिका दाखिल करना,

२. चुनावों का बहिष्कार करना,

३. और चुनाव आयोग पर जनदबाव बनाना।

इन विकल्पों में से एक या अधिक कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं।

पुलिस हमारी जासूसी कर रहे हैं, बेडरूम में घुसकर निगरानी की गई-कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप



रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस उन पर नज़र रख रही है। उनका कहना है कि वे नाना चौक स्थित सर्वोदय आश्रम में ठहरते हैं और पुलिस लगातार वहां निगरानी कर रही है।

शुक्रवार सुबह साढ़े कपड़ों में एक पुलिसकर्मी सीधे उनके बेडरूम में घुस गया, और वहां जांच-पड़ताल करने लगा। यह घटना तीसरी बार घटी है। सपकाळ ने सवाल उठाया - किसके आदेश पर मेरी जासूसी की जा रही है?

विरोधी नेताओं पर पाळत - बीजेपी की नीति : सपकाळ टिलक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सपकाळ ने बताया कि पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा - क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? पत्रकार आए हैं क्या? जब उनसे सवाल किया गया कि आप बेडरूम में क्यों घुसे? किसके आदेश हैं?, तो उसने कहा - वरिष्ठों के आदेश हैं, उनसे फोन पर बात कीजिए।

सपकाळ ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर नज़र रखने की यह नीति गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। उन्होंने कहा - पहले पेगासस से फोन टैपिंग की गई, फिर सीधी निगरानी शुरू की गई, और अब वे हमारे बेडरूम तक पहुँच गए हैं। लेकिन ऐसी दमनकारी हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं।

पवई एनकाउंटर पर सवाल सपकाळ ने पवई एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए, जिसमें पुलिस ने रोहित आर्य नामक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसने १७ बच्चों को बंधक बनाया था।

उन्होंने कहा - बच्चों की जान बचाना ज़रूरी था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह गोली चलाई, उस पर संदेह है। जब एनएसजी की टीम मौके पर थी, तब गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी?

सपकाळ ने बताया कि रोहित आर्य को मानसिक रोगी बताया जा रहा है, जबकि वह पहले 'सुंदर माझी शाळा' जैसे सरकारी अभियानों से जुड़ा था और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर के साथ मंच साझा कर चुका था। उन्होंने इस एनकाउंटर की जांच की मांग की।

फडणवीस गुंडों के आका हैं - सपकाळ सपकाळ ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संपदा मुंडे को दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ी, जो वास्तव में हत्या है।

इस मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीतसिंह नाइक-निंबालकर का नाम सामने आया है। सपकाळ ने कहा - उन्होंने कई लोगों को परेशान किया है, अपहरण, मारपीट और रंगदारी जैसे मामलों में शामिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें बिना जांच के क्लीन चिट दे दी।

उन्होंने यह भी कहा कि सिंधुदुर्ग ज़िले के बांदा में फूल विक्रेता ने भी बीजेपी नेताओं के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की, और वीडियो छोड़कर आरोप लगाए।

सपकाळ ने कहा - राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी भी। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस सीधे जिम्मेदार हैं - वे अपराधियों के सरगना बन गए हैं। शिवसेना और भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल अकोला ज़िले में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता विजय मालोकार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया।

उन्होंने तीन बार विधानसभा चुनाव लड़ा है और सरकार की कई समितियों में काम किया है। इसके अलावा, शिवसेना (उद्धव गुट) के सहसंपर्क प्रमुख और हिंगोली ज़िले के नेता डॉ. रमेश शिंदे पाटिल ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया।

इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस, युवासेना, भाजपा और शेतकरी संघटना के कई पदाधिकारी भी कांग्रेस में शामिल हुए।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

स्व.संपदा ताई के न्यायिक संघर्ष की पहली सीढ़ी, यहीं नहीं रुकना, तब तक चैन से नहीं बैठना-धनंजय मुंडे

मुंबई (प्रतिनिधि) – सातारा जिले के फलटण में स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत और मूल रूप से बीड जिले के वडवणी तालुका की महिला डॉक्टर संपदा मुंडे की आत्महत्या मामले में गहन जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी समिति गठित कर जांच करने के निर्देश आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। स्व. संपदा ताई, जो अपनी बहन हैं, उनके न्याय के लिए उठाए गए संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है और यह संघर्ष यहीं नहीं रुकेगा, ऐसा मत पूर्व मंत्री विधायक धनंजय मुंडे ने एक्स पोस्ट के माध्यम से व्यक्त किया है।

२३ अक्टूबर को भाऊबीज की रात को डॉ. संपदा मुंडे ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की थी।

स्व. डॉ. संपदा ताई मुंडे आत्महत्या मामले में महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी समिति गठित कर जांच के मुख्यमंत्री के निर्देश

लेकिन परिवार ने इसे संदिग्ध बताया, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ लिया। इस बीच पूर्व मंत्री विधायक धनंजय मुंडे ने मृतका डॉ. संपदा के परिजनों से वडवणी तालुका के कौडगाव में सांवना भेंट की, जिसके बाद परिजनों ने डॉ. संपदा की मौत को लेकर कई संदेह व्यक्त किए। संपदा ताई ने चिकित्सा सेवा के दौरान उन पर विभिन्न मामलों में दबाव डालकर तरह-तरह से परेशान किया गया तथा शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न किया गया, यह बात उन्होंने कई बार विभिन्न



शिकायतों के माध्यम से शासन-प्रशासन इसकी अनदेखी कर यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया तथा उनकी

आत्महत्या भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। इसलिए मौत से पहले और बाद की कई घटनाएं संदिग्ध हैं, ऐसा मत धनंजय मुंडे ने व्यक्त किया था। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र एसआईटी समिति गठित की जाए, इसमें सातारा जिले में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त न किए जाएं तथा वस्तुनिष्ठ जांच हो और संपदा की मौत के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को कठोर सजा हो, ऐसी अपेक्षा मुंडे ने राज्य

के मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष व्यक्त की थी।

इस बीच इस मामले में स्व. डॉ. संपदा के परिजनों सहित कई सामाजिक व राजनीतिक दलों के नेताओं ने आवाज उठाई है और आज मांग के अनुरूप एसआईटी समिति गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग को दिए हैं।

स्व. संपदा मुंडे के न्याय की लड़ाई में यह पहला कदम है तथा डॉ. संपदा, जो अपनी बहन हैं, उन्हें प्रताड़ित करने वाले हर अपराधी को सलाखों के पीछे डालने तक मैं या इस लड़ाई में शामिल कोई भी शांत व चैन से नहीं बैठेगा, ऐसा मत धनंजय मुंडे ने अपनी एक्स पोस्ट के माध्यम से व्यक्त किया है।

सांसद बजरंग सोनवणे की पहल से शुरू हुई सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया

२८ अक्टूबर को मंत्री जयकुमार रावल को लिखा था पत्र

बीड: इस वर्ष बीड ज़िले में भारी बारिश के कारण खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। बावजूद इसके कुछ किसानों को सोयाबीन जैसी फसलें सीमित मात्रा में मिली हैं। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए थे, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए सांसद बजरंग सोनवणे ने २८ अक्टूबर को सहकार, विपणन और वस्त्र उद्योग मंत्री जयकुमार रावल को एक पत्र भेजकर किसानों के लिए तत्काल सोयाबीन खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की थी।



इस पत्र के बाद सहकार, विपणन और वस्त्र उद्योग विभाग ने सोयाबीन, मूंग और उड़द की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (चड्डा) पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीड ज़िले में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है। वर्तमान में फसल की कटाई और मड़ाई पूरी हो चुकी है, ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य के अनुसार दर मिलना आवश्यक है। सांसद सोनवणे ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि – बीड ज़िले के अधिकांश किसान सोयाबीन उत्पादक हैं। इस सीज़न में बारिश का मिज़ाज अस्थिर रहा, फिर भी किसानों ने कड़ी मेहनत से फसल

तैयार की। वर्तमान में बाज़ार भाव में गिरावट आई है, जिससे किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार को तुरंत खरीदी केंद्र शुरू करने चाहिए ताकि किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें। सांसद बजरंग सोनवणे पूरे राज्य में किसान पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। किसानों से जुड़े मुद्दों को न केवल गंभीरता से उठाते हैं बल्कि संसद में भी सक्रिय रूप से आवाज़ उठाते रहते हैं। जब भी ज़िले के किसान किसी मुसीबत में होते हैं, सोनवणे सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं – यही कारण है कि किसानों में उनके प्रति गहरा विश्वास है। पिछले महीने की भारी बारिश ने ज़िले में फसलों और कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचाया। फिर भी जिन किसानों को कुछ सोयाबीन की उपज मिली है, उन्हें उसका उचित दाम मिले, इसी उद्देश्य से खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की गई थी। अब सरकार ने मंजूरी देते हुए २०२५-२६ के खरीदी हंगाम में सोयाबीन, मूंग और उड़द की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत किसानों की ऑनलाइन नोंदणी ३० अक्टूबर २०२५ से ३१ दिसंबर २०२५ तक की जाएगी। वहीं, १५ नवंबर २०२५ से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अगले ९० दिनों तक खरीदी प्रक्रिया चलाई जाएगी।

किसानों के भरोसे से ही जय भवानी की प्रगति संभव हुई-चेयरमैन अमरसिंह पंडित

जय भवानी सहकारी शुगर फैक्ट्री के ४३वें गळीत हंगाम (क्रशिंग सीज़न) का शुभारंभ मान्यवरों के हाथों सम्पन्न

गेवराई, ३१ अक्टूबर (प्रतिनिधि): चेयरमैन अमरसिंह पंडित ने कहा कि – संस्थान के हित के लिए कई बार लोकप्रियता से परे रहकर कठोर निर्णय लेने पड़े, अनेक लोगों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी, लेकिन कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी कारण किसानों का विश्वास जीतने में सफलता मिली। किसानों के भरोसे की बदौलत ही 'जय भवानी' की प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि कारखाना अब अपने ५०वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और इस अवसर पर इसकी ग़ज़ा पेराई क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ इसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। इन्हें हंगाम में ९ लाख मीट्रिक टन ग़ज़ा पेराई का लक्ष्य रखा गया है, और जब तक सभी पंजीकृत ग़त्रे की पेराई पूरी नहीं होती, तब तक कारख़ाने की मशीनें बंद नहीं होंगी। यह वक्तव्य चेयरमैन अमरसिंह पंडित ने जय भवानी सहकारी साख़र कारख़ाना (जय भवानी सहकारी शुगर फैक्ट्री) के ४३वें गळीत हंगाम के उद्घाटन अवसर पर दिया, जिसका शुभारंभ

नारायणगड संस्थान के महंत ह.भ.प. शिवाजी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव (दादा) पंडित और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों हुआ। कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुक्रवार, ३१ अक्टूबर को हुए इस कार्यक्रम में जय भवानी सहकारी शुगर फैक्ट्री का नया गळीत हंगाम बड़े उत्साह से शुरू हुआ। इस अवसर पर महंत शिवाजी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव पंडित, चेयरमैन अमरसिंह पंडित, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब नाटकर, कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति के सभापति जगन्नाथ काळे, उपसभापति श्रीहरी पवार, भवानी बैंक के अध्यक्ष बप्पासाहेब मोटे, ख़रेदी-विक्री संच के अध्यक्ष जयदीप ओटी, तथा रिपार्ई पार्टी के तालुकाध्यक्ष किशोर कांडेकर समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति, जय भवानी के पूर्व और वर्तमान संचालक तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में महंत शिवाजी महाराज और वरिष्ठ संचालक राजेंद्र वारंगे ने विधिवत गव्हाण पूजन किया।



चेयरमैन अमरसिंह पंडित का संबोधन चेयरमैन पंडित ने कहा – जय भवानी सहकारी शुगर फैक्ट्री इस वर्ष अपने स्वर्ण जयंती (५०वें वर्ष) में प्रवेश कर रही है। पिछले ५० वर्षों में फैक्ट्री ने अपेक्षा से अधिक प्रगति की है। आदणीय शिवाजीराव दादा का सपना आज साकार हुआ है। किसानों, कर्मचारियों, मजदूरों, संचालकों और शुभचिंतकों के सहयोग से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि शिवछत्र परिवार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं जनता के विश्वास के बल पर ही टिक सकी हैं। जनता के विश्वास ने ही जय भवानी को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग में कई तकनीकी नवाचार किए गए हैं, जिनकी सराहना राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। इस वर्ष कार्यक्षेत्र में लगभग १३ लाख मीट्रिक टन ग़त्रे की खेती हुई है, और फैक्ट्री में पंजीकृत सभी ग़त्रे की पेराई के लिए प्रबंधन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंदफणा नदी पर टाकळगांव बैराज की स्वीकृति और जायकवाडी प्रोजेक्ट (पैठण उजवा कालवा, टप्पा २) की मंजूरी से किसानों को काफी लाभ होगा। तकनीकी और आर्थिक जानकारी प्रास्ताविक भाषण में फैक्ट्री के जनरल मैनेजर

दत्तात्रय रेकाळे ने बताया कि इस वर्ष फैक्ट्री ने हार्वेस्टर मालिकों के साथ अनुबंध किए हैं, जिसके तहत प्रतिदिन २००० मीट्रिक टन ग़ज़ा हार्वेस्टर से काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चीनी को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है, इसलिए किसानों को भी ग़त्रे का अच्छा दाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बगास (ग़त्रे का अवशेष) और अन्य उप-उत्पादों से आय बढ़ाने पर फैक्ट्री प्रशासन कार्य कर रहा है, जिससे इस वर्ष राज्यस् में वृद्धि की उम्मीद है। महंत शिवाजी महाराज का आशीर्वाचन महंत शिवाजी महाराज ने अपने आशीर्वाचन में कहा कि – शिवाजी दादा ने गरीबों की सेवा की, अनेक संस्थाएं स्थापित कर जनता का भला किया। उनकी आने वाली पीढ़ी भी इन संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए कार्य कर रही है। कर्मचारियों और किसानों का सम्मान कार्यक्रम के दौरान फैक्ट्री साइट पर सबसे पहले पहुंचने वाले वाहन मालिकों का नकद

पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। ट्रैक्टर मालिक अशोक पवार और शामराव पवार को महंत शिवाजी महाराज और चेयरमैन अमरसिंह पंडित ने नकद पारितोषिक प्रदान किया। चेयरमैन पंडित ने फैक्ट्री कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति कार्यक्रम में संचालक जगन्नाथ शिंदे, कुमारराव ढाकणे, सुनील पाटील, श्रीराम आरगडे, अप्पासाहेब गव्हाणे, नारायणराव नवले, संभाजी पवळ, गणपत नाटकर, संदिपान दातखिळ, जगन्नाथ दिवान, शरद चव्हाण, भिमराव मोरे, रावसाहेब देशमुख, बाबुराव काकडे, रहेमतुल्ला पठाण, शंकरबप्पा तौर, साहेबराव चव्हाण, डॉ. विजयकुमार घाडगे, माजी उपसभापती विकास सानप, बिपीन डरफे, कार्यकारी संचालक राजेंद्र खाडप, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, ग़ज़ा उत्पादक किसान, सदस्य, ठेकेदार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनेक पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।